इकाई 30 1937 के चुनाव तथा कांग्रेस मंत्रिमंडल

इकाई की रूपरेखा

30.0 उद्देश्य
30.1 प्रस्तावना
30.2 संवैधानिकता की ओर
30.3 चुनाव
  30.3.1 स्थानीय निकायों के चुनाव
  30.3.2 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन
  30.3.3 चुनाव घोषणा पत्र
  30.3.4 फैज़पुर अधिवेशन
30.4 1937 के चुनाव
  30.4.1 उम्मीदवारों का चयन
  30.4.2 चुनाव अभियान
  30.4.3 चुनाव परिणाम
30.5 पद स्वीकरण
30.6 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कामकाज
  30.6.1 राजनीतिक क़ैदी और नागरिक स्वतंत्रताएं
  30.6.2 किसानों का सवाल
  30.6.3 मज़दूर वर्ग
  30.6.4 रचनात्मक कार्यक्रम
  30.6.5 कांग्रेस के समाने आई कुछ समस्याएं
30.7 सारांश
30.8 शब्दावली
30.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

30.0 उद्देश्य

पिछली इकाई 29 में हम यह जान चुके हैं कि 1935 के ऐक्ट के द्वारा किस तरह संवैधानिक सुधार लागू किये गये। इन सुधारों के बारे में कांग्रेसियों में मत भिन्नता थी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- संवैधानिक सुधारों के मसले पर कांग्रेसियों के बीच प्रचलित विभिन्न मतों के बारे में जानेंगे,
- 1937 के चुनाव और उनसे संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में जानेंगे,
- 1937-39 के दौरान बहुत से प्रांतों में पदारूढ़ कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्य-कलापों के बारे में जानेंगे,
- इस दौरान कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के सामने आई समस्याओं को समझेंगे, और
- इन मंत्रिमंडलों के इस्तीफ़े के कारणों को समझ सकेंगे।

30.1 प्रस्तावना

यह इकाई वर्ष 1936-39 के दौर के राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रकाश डालती है। यह वह दौर था जब कांग्रेस ने आंदोलन और जन संघर्षों का रास्ता छोड़ दिया था, और दूसरी बार संवैधानिक राजनीति के चरण में प्रवेश किया था। लेकिन, पहले के स्वराजवादी चरण के

विपरीत, इस बार कांग्रेस का इरादा संवैधानिक तरीक़ों का परीक्षण करना था। इसी के अनुरूप कांग्रेसियों ने अपनी सफलता के लिए काम किया। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि संवैधानिक तरीक़ा अपनाने के सवाल पर कांग्रेसियों में मतभेद नहीं थे। दरअसल कांग्रेस द्वारा लिए गये किसी भी निर्णय पर अमल से पहले ज़ोरदार बहस होती थी। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई के मूल सवाल पर सहमति थी, फिर भी इस लड़ाई के लिए अपनाये जाने वाले तरीक़ों को लेकर कांग्रेसियों में विवाद था। यह वही समय था जब वाम-पक्ष कांग्रेस के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वामपक्ष और दक्षिणपक्ष विभिन्न मसलों पर वाद-विवाद और बहस करते थे। एक उत्तेजक बहस के बाद कांग्रेस ने 1937 में चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया और उसे सात प्रांतों में सरकार बनाने में सफलता मिली।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने दो वर्ष से कुछ ही अधिक समय तक काम किया। सत्ता में रहने की अल्पावधि में उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ा। अलग-अलग सामाजिक वर्गों की कांग्रेस से अलग-अलग अपेक्षाएं थीं, इसलिए जब कांग्रेस सत्ता में आयी तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गयीं। कांग्रेस जिन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध थी, उनमें से कुछ निश्चित सिद्धातों को अमल में लाने में सफल हुई। लेकिन ऐसे भी मसले थे जिन पर कांग्रेस भीतर से विभाजित थी।

हालांकि कांग्रेस मंत्रिमंडला ने सितम्बर, 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया, इसका दो साल तक सत्ता में बना रहना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।

30.2 संवैधानिकता की ओर

नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण ने (1932 से आगे) लोगों को उस तरह आंदोलित नहीं किया जैसा कि पिछले चरण ने किया था। यह साफ़ दिखाई देने लगा था कि इस बार का जन आंदोलन अधिक दूर तक नहीं खिंचेगा। जन आंदोलन की इस शिथिलता से कांग्रेस के भीतर से संवैधानिक तरीक़ों की ओर लौटने की आवाज़ें उठने लगीं। कुछ हिस्सों में स्वराजपार्टी को पुनर्जीवित करने की बात भी चलाई गयी। आसिफअली और एस. सत्यमूर्ति इस सवाल को आंदोलन के दौरान ही गांधीजी के सामने उठा चुके थे। एक और प्रमुख कांग्रेसी डा. एम. ए. अंसारी परिषद में प्रवेश के पक्षधर थे। 1933 में सत्यमूर्ति ने मद्रास स्वराज पार्टी का गठन किया। के. एम. मुंशी, बी. सी. राय, और रामास्वामी आयंगर ने भी स्वराज पार्टी की पुनर्स्थापना के लिए गांधीजी की सहमति प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन, इस बिंदु पर गांधीजी संवैधानिक तरीक़े पर लौटने के विचार के पक्ष में नहीं थे। मगर उन्होंने इन लोगों से कहा:

> "अगर इस क़दम (संवैधानिक तरीक़े की ओर वापसी) में आपका भरोसा है, तो आप इसका समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

कुछ कांग्रेसी परिषद प्रवेश के पक्ष में थे तो आचार्य नरेन्द्रदेव और पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे अन्य लोग इसके विरोध में थे। इससे कांग्रेस के भीतरी मतभेदों का खुलासा होता है। प्रत्येक पक्ष कांग्रेस की नीति को प्रभावित करने और अपनी ओर झुकाने के लिए उत्सुक था। लेकिन दोनों ही पक्ष यह काम गांधीजी की सहमति से ही करना चाहते थे। जैसे ही नागरिक अवज्ञा-आंदोलन को वापस लिया गया, गांधीजी ने प्रत्येक पक्ष को यह कह के मन मुताबिक़ क़दम उठाने के लिए स्वतंत्र कर दिया:

> "मैं चाहता हूँ कि सभी वर्ग सभी दिशाओं में एक ही लक्ष्य की ओर बिना एक दूसरे की आलोचना किये अपने-अपने तरीक़ों से काम करें।"

चित्र 5. सत्यमूर्ति

जो वर्ग इस समय परिषद प्रवेश (council entry) का समर्थन कर रहा था वह ठीक उन तर्कों पर नहीं चल रहा था जो इससे 12 वर्ष पूर्व स्वराजवादियों ने प्रस्तुत किये थे। जैसा कि आपने इकाई 21 में पढ़ा है कि स्वराजवादियों ने परिषदों में प्रवेश, संविधान को अंदर से ध्वस्त करने के लिए किया था और उन्होंने पद स्वीकार नहीं किये थे। लेकिन इस बार

राजगोपालाचारी जैसे नेता जिस परिषद प्रवेश की बात कर रहे थे वह स्वराजवादियों से दो रूपों में अलग था :

1 इसका उद्देश्य संविधान को ध्वस्त करना था। इसके सहज काम करने में रुकावटें खड़ी करना नहीं था। उनका उद्देश्य संविधान को कार्य योग्य बनाना था।
2 बहुमत हासिल कर लेने की स्थिति में शासन भार स्वीकार करना और मंत्रिमंडलों का गठन करना था।

चित्र 6. पुरुषोत्तम दास टन्डन

दूसरी ओर समाजवादी झुकाव वाले कांग्रेसी थे जो परिषद प्रवेश के विरोधी थे और संविधान को काम करने योग्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। आप पहले ही पढ़ चुके हैं (इकाई सं० 27) कि समाजवादियों ने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके ख़ुद को किस प्रकार संगठित किया था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये मतभेद हालांकि सैद्धांतिक झुकावों से प्रेरित-नियंत्रित थे, फिर भी ये कांग्रेस के अंदर आंतरिक मसले समझे जाते थे। जहां तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कांग्रेस के रवैये का सवाल था, यह हमेशा एक स्वर में प्रकट किया जाता था। उदाहरण के लिए, 1935 ऐक्ट के आपत्तिजनक खंडों की भर्त्सना कांग्रेस ने सभी वर्गों के पूरे समर्थन से की (आपने इस ऐक्ट के विरोध के बारे में इकाई 29 में पढ़ा है)।

कांग्रेस के सामने प्रमुख मसला यह निर्णय लेना था कि आगामी चुनावों में भाग लिया जाय और पद भार स्वीकार किया जाय या नहीं। हम अगले भाग में देखेंगे कि इन मसलों के संदर्भ में कांग्रेस ने अपनी नीति को किस तरह गढ़ा।

बोध प्रश्न 1

1 परिषद-प्रवेश के समर्थकों के विचार किस तरह से स्वराजवादियों के विचारों से भिन्न थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2 निम्न में से कौन सा कथन सही या ग़लत है। ($\surd$) या ($\times$) चिन्ह लगाइए।

i) नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण ने भी लोगों को उतना ही आंदोलित किया जितना कि पहले चरण ने। ☐

ii) 1933 में गांधीजी ने संवैधानिक तरीक़ों की ओर वापसी के विचार का समर्थन किया। ☐

iii) परिषद प्रवेश को लेकर कांग्रेस के अंदर मतभेद थे। ☐

iv) जब कभी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई क़दम उठाना होता था तो कांग्रेस का स्वर एक होता था। ☐

v) आचार्य नरेन्द्रदेव ने परिषद प्रवेश का समर्थन किया। ☐

30.3 चुनाव

इससे पहले हम 1937 के चुनाव और उनसे संबधित घटनाओं के विश्लेषण को आगे बढ़ायें, हम उस समय की आम राजनीतिक स्थिति और कुछ पूर्व-चुनावों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। काफ़ी बहस और वाद-विवाद के बाद कांग्रेस ने अपने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में प्रांतीय परिषदों के लिए होने वाले आगामी चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। लेकिन

इससे पहले अक्टूबर 1934 में गांधीजी ने कांग्रेस की 4 आने की सदस्यता को त्याग कर खुद को कांग्रेस से हटा लिया था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि कांग्रेस में उनका प्रभाव कम हो गया था या उन्होंने कांग्रेस की नीति को निर्देशित करना बंद कर दिया था। चाहे गांधीजी कांग्रेस के चार आने वाले सदस्य रहे हों या न रहे हों, कांग्रेस में उनका वर्चस्व लगातार बना रहा।

30.3.1 स्थानीय निकायों के चुनाव

जैसा कि पहले कहा जा चुका है गांधीजी ने सभी वर्गों को अपने-अपने ढंग से काम करने की आज़ादी दे दी थी बशर्ते कि वे एक ही लक्ष्य को लेकर यानी ब्रिटिश शासन के विरोध में काम करें। इस प्रकार 1934 से कांग्रेस ने विधानसभा या स्थानीय निकायों के चुनावों में जब भी, जैसे भी हुआ भाग लेना शुरू किया। ये चुनाव निम्न दृष्टिकोणों से लाभदायक साबित हुए:

1 चुनाव परिणामों के माध्यम से कांग्रेस अपने जनाधार की परीक्षा कर सकती थी।
2 इन चुनावों ने कांग्रेस को चुनावों के संगठन, नियोजन और प्रबंध के मामले में बहुत बड़ा अनुभव दिया।
3 कांग्रेस, निर्वाचन राजनीति में आवश्यक कोष के लिए अपने सहयोगियों की परीक्षा ले सकती थी।

यहां हम मद्रास प्रेसीडेंसी में हुए चुनावों का उल्लेख कर सकते हैं। मई 1935 में स्थानीय चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन के उद्देश्य से एक कांग्रेस नागरिक बोर्ड (civic board) का गठन किया गया। उम्मीदवारों को परिषद द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी (देखिये डेविड आरनाल्ड द कांग्रेस इन तमिलनाडु) इसमें निम्न काम करना शामिल था :

- स्वदेशी को प्रोत्साहन,
- भ्रष्टाचार दूर करना.
- चिकित्सा और शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार, इत्यादि।

इन स्थानीय चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक थे। मदुरई में नगरपालिका (अक्तूबर 1935) में कांग्रेस ने 36 में से 21 सीटों पर विजय प्राप्त की और एक वर्ष बाद (अक्टूबर 1936) मद्रास में 40 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीतीं। इसी प्रकार केन्द्रीय विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने मद्रास में मतदाताओं के सामने निम्न मुद्दे उठाये:

1 कांग्रेस को वोट देकर उन्हें कांग्रेस के प्रति अपना निरंतर समर्थन ज़ाहिर करना चाहिए,
2 सरकार को यह दिखाना चाहिए कि तमाम दमन के बावजूद कांग्रेस जीवंत बनी हुई है,
3 वे चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं।

जब परिणामों की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने इस प्रांत में जिन सात सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी को जीत कर जस्टिस पार्टी का सफ़ाया कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 76 सीटों में से कांग्रेस के उम्मीदवार 55 सीटों पर खड़े हुए और 44 पर जीते। कुल मतदान 650,000 था और कांग्रेस को 375,000 मत मिले।

कांग्रेस ने प्रांतीय परिषदों के चुनावों में भाग लेने के पक्ष में निर्णय लेने में लम्बा समय लगाया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी अगस्त 1975 की बैठक में फैसला किया कि चुनावों में भाग लेने का मसला लखनऊ अधिवेशन में हल किया जायेगा।

30.3.2 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन

लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उनके अध्यक्षीय भाषण में समाजवाद की वकालत की गई थी जिसे वे "विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं के लिए एकमात्र हल" मानते थे। उन्होंने कांग्रेस की सीधी कार्रवाई के संघर्षों में लोगों की भूमिका की सराहना की लेकिन आत्म आलोचना की टिप्पणी के रूप में उन्होंने कहा:

> "हमारी राजनीति और विचार बड़ी सीमा तक···· जनता के बहुत बड़े भाग की आवश्यकताओं के विचार से नहीं बल्कि मध्यवर्गीय दृष्टिकोण से नियंत्रित होते हैं"।

चित्र 7. लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का जुलूस

उनके अनुसार लोगों तक पहुंचने का रास्ता यह था कि "जनता के दिन-प्रतिदिन के संघर्ष उनकी आर्थिक मांगों और अन्य परेशानियों के आधार पर चलाये जाने चाहिए"। नेहरू ने तीन समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव और अच्युत पटवर्धन को कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया। इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव पारित किये गये। उनमें से प्रमुख ये थे:

i) "राज्यों (देशी रियासत-रजवाड़े) की जनता को भी आत्मनिर्णय का वही अधिकार होना चाहिए जो कि शेष भारत की जनता को है और यह कि कांग्रेस भारत के सभी भागों के लिए समान राजनीतिक, नागरिक, और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करती है"। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राज्यों के लोगों को "अपनी आज़ादी का संघर्ष, स्वयं चलाना चाहिए" (इसके बारे में अधिक जानकारी आप इकाई 32 में प्राप्त करेंगे)।

ii) कांग्रेस की प्रान्तीय इकाइयों से कहा गया कि वे किसानों की समस्या संबंधी जानकारी प्राप्त करें ताकि इसके आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए० आई० सी० सी०) को अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिल सके।

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तथापि, पद स्वीकार करने का निर्णय स्थगित रखा गया। यह ऐसा मसला था जिस पर कांग्रेस के भीतर काफ़ी तेज़-तीखी बहसें हुईं। उदाहरण के लिए, टी० प्रकाशम और सत्यमूर्ति ने पद स्वीकार करने की ज़ोरदार वकालत की। जबकि एम० आर० मसानी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा:

> "हमसे कहा जाता है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल सरकारी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय झंडा फहराने में कामयाब होगा। जिस दिन राष्ट्रीय झंडा यूनियन जैक के नीचे फहराया जायेगा, हमारा झंडा प्रदूषित हो जायेगा हमें नये राष्ट्रीय झंडे की खोज करनी पड़ेगी।"

वास्तव में चुनाव लड़ने और पद स्वीकारने को स्थगित करने का निर्णय, पद स्वीकार करने के पक्षधरों और चुनाव का बहिष्कार करने की मांग करने वालों के बीच एक प्रकार का समझौता था। फिर भी नेतृत्व का एक ऐसा वर्ग था जिसका विश्वास था कि पद स्वीकारने

पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मद्रास में मुदलियार और सत्यमूर्ति और मध्यप्रांत (सेंट्रल प्राविन्स) में डॉ. खरे और बहुत से अन्य नेता सोचते थे कि पद स्वीकारने संबंधी घोषणा से चुनाव जीतने की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी। कुछ हिस्सों में पद स्वीकारने और भावी मुख्य मंत्रियों संबंधी बातचीत भी शुरू हो गयी थी। लेकिन जैसा कि राजगोपालाचारी ने कहा:

"कांग्रेस ने एक बार फिर एक संयुक्त मोर्चे के रूप में अपनी क्षमता प्रदर्शित कर दी है। वाद-विवाद में बने पक्षों को विभाजन नहीं समझा जाना चाहिए। वे सामूहिक चिंतन के सामान्य उपकरण हैं।"

२० मीरगंज
इलाहाबाद

प्रिय भाई,

संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी ३ मई की बैठक में एक किसान समिति निम्नलिखित सज्जनों की मुक़र्रर की है :—

श्री० पुरुषोत्तम दास टण्डन, श्री० गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री० सम्पूर्णानन्द, श्री० वेंकटेश नारायण तिवारी, लालबहादुर।

समिति को यह कार्य सौंपा गया है कि वह उन कारणों का पता लगावे जिनसे किसानों की दशा इस समय इतनी ख़राब हो गयी है, और साथ ही उन उपायों को बतावे जिनसे उनकी मौजूदा हालत में सुधार हो सकता है। प्रान्तीय कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक़ इस समिति को ३० जून तक ऐसी संस्थाओं से जो किसानों के काम में दिलचस्पी रखती है, रिपोर्ट मँगा लेनी है।

इस समिति ने जाँच करने की सुविधा के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है जिसकी एक प्रति आप के पास साथ भेजती हूँ। आप से निवेदन है कि उक्त समय तक इस प्रश्नावली में से जितने सवालों का जवाब दे सकें, स्वीकार दें। अगर किसी सवाल का जवाब न दे सकें, तो लिखिए कि किस वजह से नहीं दे सकते। जवाब देने में हर शीर्षक और उसकी अन्तर्गत संख्या का हवाला दीजिएगा ताकि यह पता लग सके कि किस सवाल का कौन सा जवाब है।

आपका
लाल बहादुर
मंत्री
किसान-समिति

हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग।

चित्र 8-यू. पी. किसान समिति द्वारा जारी किया गया एक पैम्फलेट

30.3.3 चुनाव घोषणा पत्र

यह संसदीय समिति का काम था कि वह कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करे। इस घोषणा पत्र का लक्ष्य कांग्रेस की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट करना था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त, 1936 में स्वीकार किये गये घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं को हम यहां बता रहे हैं।

i) घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कहा गया था कि कांग्रेसियों को मंत्रिमंडल में भेजने का उद्देश्य सरकार से सहयोग करना नहीं, बल्कि 1935 के ऐक्ट के विरुद्ध लड़ना और

चित्र 9. राजगोपालाचारी

इसे समाप्त करना है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को "भारत में अपनी जड़ें मज़बूत करने के प्रयासों" से रोका जाना चाहिए।

ii) इसने भारतीय जनता, विशेषकर किसानों, मज़दूरों और कारीगरों की ग़रीबी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया और कहा "अपने देश के करोड़ों लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य हमें अपनी आर्थिक, सामाजिक समस्याएं हल करने और अपनी जनता की गरीबी दूर करने का अधिकार दे सकता है।"

iii) कांग्रेसी प्रतिनिधियों का काम भारतीय जनता का दमन करने वाले विभिन्न कानूनों, अध्यादेशों और अधिनियमों को समाप्त करने के लिए हर सम्भव कदम उठाना था। उन्हें ये काम करने थे:

- नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना।
- राजनीतिक कैदियों और नज़रबंदों की मुक्ति।
- किसानों के प्रति किये गये अन्याय का निराकरण करना इत्यादि

iv) औद्योगिक मज़दूरों के संबंध में कांग्रेस की नीति, उनके लिए निम्न स्थितियां प्राप्त करना था।

- बेहतर जीवन स्तर।
- काम के घंटे निश्चित करना।
- श्रम की दशाओं में सुधार लाना।

इनके साथ ही ये बातें भी शामिल थीं:

- संगठन (यूनियन) बनाने का अधिकार।
- मालिकों के साथ विवादों को निपटाने के लिए उचित तंत्र विकसित करना।
- वृद्धावस्था के कारण आर्थिक दुष्परिणामों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना इत्यादि।

घोषणा पत्र में अन्य अनेक वादे किये गये थे, जैसे कि

- छुआछूत दूर करना
- महिलाओं के लिए समान अधिकार।
- खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन।
- साम्प्रदायिक समस्याओं का संतोषजनक समाधान इत्यादि।

पद स्वीकार करने के मसले को चुनाव के बाद तय किया जाना था। इस तरह कांग्रेस स्वयं को चुनावों के लिए तैयार कर रही थी और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी।

लखनऊ अधिवेशन एक अन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। इसी अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई।

30.3.4 फ़ैज़पुर अधिवेशन

कांग्रेस का अगला अधिवेशन फ़ैज़पुर में दिसम्बर, 1936 में दुबारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में बहुत से मसले उठाये गये। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही स्थितियों से संबंधित थे। नेहरू ने अपने भाषण में फासीवाद पर हमला किया और कांग्रेस ने एबीसीनिया पर इटली के हमले और चीन पर जापान के हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने विश्वयुद्ध की स्थिति में भारत के संस्थानों को ब्रिटिश द्वारा उपयोग में लाने के विरुद्ध लोगों को चेतावनी दी। राष्ट्रीय मसलों पर नेहरू ने स्पष्ट किया कि:

> "कांग्रेस की नीति की तार्किक परिणति केवल यह है कि उसे पद और मंत्रिमंडल से कुछ लेना-देना नहीं। इस नीति से किसी भी तरह अलग हटने का मतलब होगा.... भारतीय जनता के शोषण में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहभागी होना"।

इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना स्वयं का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा के निर्माण की मांग उठायी। पद स्वीकार करने के सवाल को फिर से टाल दिया गया। फैज़पुर अधिवेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस ने उठाया वह था एक कृषि कार्यक्रम को स्वीकृति देना। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में निम्न बातें शामिल थीं।

- लगान और माल गुज़ारी में 50 प्रतिशत की कमी,
- अनउपजाऊ ज़मीन को लगान और भूमि कर से मुक्त करना,
- कृषि आय पर कर लगाना,
- सामंतो उगाही और ज़बरिया मज़दूरी का उन्मूलन,
- सहकारी खेती,
- बक़ाया लगान को समाप्त करना,
- बेदख़ली क़ानूनों को आधुनिक बनाना,
- किसान संगठनों (किसान सभा) आदि को मान्यता देना।

यह कार्यक्रम ज़मींदारी और तालुकेदारी प्रथाओं के उन्मूलन के मामले पर चुप्पी साध गया था। किसान सभा के नेताओं ने आमतौर पर इस कार्यक्रम का स्वागत किया। लेकिन ज़मींदारी उन्मूलन के सवाल पर इसकी आलोचना की क्योंकि वे ज़मींदारी और तालुकेदारी जैसी प्रथाओं को किसानों के शोषण का मूल कारण मानते थे। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने उनका समर्थन किया। यहां यह बताना ज़रूरी है कि कांग्रेस का दक्षिण पक्ष ज़मींदारी उन्मूलन के पक्ष में नहीं था। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कृषि कार्यक्रम एक प्रगतिशील क़दम था और जैसा कि हम बाद में जानेंगे, इसने किसानों को कांग्रेस के पीछे लाने में दूरगामी भूमिका निभायी।

इस समय तक कांग्रेस की सदस्यता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। उदाहरण के लिए, मई 1936 में कांग्रेस के 4,50,000 सदस्य थे, जो दिसम्बर, 1936 तक बढ़कर 6,36,000 हो गये थे।

बोध प्रश्न 2

1 स्थानीय निकायों (संस्थाओं) के चुनाओं में भाग लेने के क्या लाभ कांग्रेस ने उठाये? उत्तर लगभग पांच पंक्तियों में दीजिए।

.....
.....
.....
.....
.....

2 पद स्वीकरण के पक्ष में दिये गये तर्कों की चर्चा लगभग पांच पंक्तियों में कीजिए।

.....
.....
.....
.....
.....

3 फ़ैजपुर कृषि कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं को लगभग दस पंक्तियों में बताइये।

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

30.4 1937 के चुनाव

कांग्रेस ने एक बार चुनाव लड़ने का फैसला किया तो प्रत्येक कांग्रेसी, कांग्रेसी प्रत्याशियों की सफलता के लिए तन-मन से जुट गया।

30.4.1 उम्मीदवारों का चयन

अब हम एक नज़र इस पर डालें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार किया। एक सामान्य प्रक्रिया यह थी कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां अपनी सिफ़ारिश के साथ उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस संसदीय बोर्ड के पास भेजेंगी, और बोर्ड इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। ऐसा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने एक मानदंड अपनाया जिनमें शामिल था कि एक प्रत्याशी को:

- कांग्रेस के अनुशासन का पालन करना चाहिए।
- कांग्रेस के कार्यक्रम का पालन करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए।

इन दो आधारभूत गुणों के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जैसे कि प्रत्याशी की:

- कांग्रेस के लिए की गयी सेवाएं,
- लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता, और
- चुनाव का खर्चा स्वयं उठा सकने की उसकी क्षमता।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों के चयन के लिए किये गये उनके गम्भीर प्रयासों के बावजूद, कुछ मामलों में जाति ने अपनी भूमिका निभायी। जाति की इस भूमिका के बारे में राजेन्द्र प्रसाद ने इस प्रकार लिखा:

> "कांग्रेस जैसे संगठन के लिए ऐसा करना लज्जाजनक है, लेकिन चुनावों में सफल होना हमारा पहला लक्ष्य था, और दूसरे, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि कांग्रेस एक व्यापक संगठन है जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं।"

चित्र 10. राजेन्द्र प्रसाद

चित्र 11. वल्लभ भाई पटेल

A L INDIA KISAN SUPPLEMENT

Kisan Movement Ensures Congress Victory

ANDHRA RYOT ASSOCIATIONS' PLEDGE: SIRDAR'S WARNING: PLEDGE CONTROVERSY & WITHDRAWAL: KISAN MOVEMENT & ELECTIONS

On January 17th Prof. N. G. Ranga, President of the All India Kisan Sabha issued the following statement to the press:—

"In pursuance of the resolution of the Second All India Kisan Congress, which has called upon al Kisan comrades to place all their organisational resources at the disposal of those Congress candidates, who pledge themselves to do their best to implement the minimum demands of the peasants, the Andhra Provincial Peasants' Association has prepared a pledge form. It expects a Congress candidate to vow to do his best to contantly radicalise and liberalise the Congress attitude towards peasants and to try to achieve the peasants' demands (as formulated by the Kisan Congress) by suitably influencing the day to day decisions of the Congress Parliamentary Party."

SARDAR VALLABHBHAI PATEL'S WARNING.

On January 20th Sardar Vallabhbhai Patel, President of the All India Congress Parliamentary Committee wrote as follows to the Presidents of the various Parliamentary Boards in the Madras Presidency with reference to the Kisan pledge mentioned above:—

Prof. Ranga is a member of the A. I. C. C. from your province and is a member of the Legislative Assembly elected on Congress ticket; that a responsible man of his position should have thought fit to circulate a pledge, which has not been approved by the A.I.C.C. amongst the candidates, who are pledged to contest elections on the Congress Manifesto is very regrettable. In my opinion, it is an act of gross indiscipline, and he should be called upon to explain his conduct and disciplinary action be taken against him forthwith."

ANDHRA RYOTS' ASSOCIATION SECRETARY'S REPLY.

On January 22nd. the Joint Secretary of the Andhra Provincial Ryots' Association issued a spirited reply to the threat of Sardar Patel for taking disciplinary action against Prof. Ranga. He stated:—

"Neither the Andhra Peasants' Association nor Mr. Ranga called upon the Congress candidates to disobey the Congress or put the interests of the Nation second to those of the peasants. Peasants are never disloyal to the Congress and they are always its loyal allies. Unlike the Trade Union Congress or the Congress Nationalist Party, the Kisan Sabha has not thought it fit to organise a separate election campaign merely because the present agrarian programme of the Congress falls far short of the Minimum Demands or because the Congress failed to state in unequivocal terms its attitude towards the abolition of the Zamindari system or absentee landlordism. In fact, the Andhra Provincial Ryots' Conference held at Nidubrole last May demanded of its President, Mr. Ranga, to organise an independent peasants' parliamentary programme. But for his lucky interyention, things would have taken an altogether different turn."

After referring to the existence of the Peasants' Group of nearly 30 members of the Indian Legislative Assembly with Dr Khan Sahib as its President, and to the agrarian programme adopted by th Indian National Congress at Faizpur, the Secretary concluded his reply as follows:—

"I may inform Sardar Patel that Mr. Ranga is not alone responsible for this pledge, but the whole Kisan Sabha, which passed their resolution, and it has within its fold many Congressmen. So the Sardar has to take wholesale disciplinary action. But before he launches upon that extreme step, he would do well to realise that this pledge, while blowing the winds off the sails of the Justice Party, which claims to have done so much for the peasants for the last ten years when they were in power, strengthens the Congress candidates, where the Congress has to encounter the Zamindari vested interest in this Presidency. If the Sardar insists on his unwise and unjust disciplinary action, the peasants will surely stick to their guns, which is not safe either for the Congress or the Kisans."

PROF. RANGA WITHDRAWS THE PLEDGE.

On January 23rd. Prof. Ranga issued the following statement:—

I have seen Sardar Vallabhbhai's statement regarding the peasants demand for a pledge from the Congress candidates to continuously liberalise the Congress attitude towards the peasants

चित्र 12. कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट (5 फ़रवरी 1937 ई०)

कुछ मामलों में चयन को लेकर विवाद भी हुए। उदाहरण के लिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में यह देखकर दु:खी थे कि जिन व्यक्तियों का चुनाव लड़ने के लिए चयन किया गया है उनमें से कुछ वास्तव में अवसरवादी थे। जिनका इससे पहले कांग्रेस से कुछ भी लेना-देना नहीं था। इसी प्रकार बम्बई में भी के० एफ० नरीमन और वल्लभ भाई पटेल के बीच मतभेद पैदा हो गये थे। आंध्र में, एन० जी० रंगा ने, आंध्र रैयत (Ryots) सघ की ओर से बोलते हुए, कांग्रेसी प्रत्याशियों से एक शपथ लेने का आग्रह किया था। यह शपथ प्रत्याशियों को विधानमंडल के अंदर और बाहर किसानों के हित के लिए काम करने से बांधती थी। बहुत से कांग्रेसी प्रत्याशियों ने इस शपथ पर हस्ताक्षर किये मगर वल्लभ भाई पटेल ने इस कदम की आलोचना की। रंगा ने यह स्पष्ट किया कि यह कदम किसी भी तरह कांग्रेस के अनुशासन के विरुद्ध नहीं है बल्कि इससे कांग्रेसी संगठन मज़बूत होगा। लेकिन पटेल अड़े हुए थे, इसलिए रंगा को यह शपथ वाला कदम वापस लेना पड़ा।

30.4.2 चुनाव अभियान

एक ज़बरदस्त चुनाव अभियान चलाकर कांग्रेस ने चुनाव में विजय प्राप्त करने की भरपूर कोशिश की। नेहरू ने कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को सलाह दी कि फैज़पुर कृषि कार्यक्रम को हमारे चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। स्वयं नेहरू ने सारे देश का दौरा किया। इलाहाबाद के ग्रामीणों में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा :

> "भारत में केवल दो दल हैं—एक जो लोगों के हित के लिए लड़ रहा है, और दूसरा इसके विरुद्ध।···· कांग्रेस, खान बहादुरों, राजा बहादुरों और नवाबों को जो कि सरकार के साथ रहे हैं, बाहर करने के लिए परिषदों में प्रवेश कर रही है।"

लोगों में एक आम भावना घर कर रही थी कि बहुत जल्दी कांग्रेसी राज, ब्रिटिश राज की जगह पर आ जायेगा। यू० पी० के गवर्नर ने कांग्रेस के अभियान के बारे में वाइसरॉय को लिखा :

'कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अपने साथ कापियां लेकर घूम रहे हैं और काश्तकारों से पूछते हैं कि वे इस समय कितना लगान दे रहे हैं? काश्तकार कहते हैं शायद दो रुपया प्रति बीघा।" कांग्रेस कार्यकर्त्ता कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोग कांग्रेस को वोट देते हो तो यह लगान घटाकर चार आने कर दिया जायेगा।" "वह इसे अपनी कापी में दर्ज कर लेता है····।"

बिहार में चुनाव ने "किसान बनाम ज़मींदार" का मोड़ ले लिया। देहात में तब तक लोकप्रिय चुनाव गीत था "मगर कोठरी में बदल जायेंगे" (इसका अर्थ यह था कि वोट डालने वाले कमरे में अपना निर्णय बदल देंगे) और यह गीत उन लोगों के द्वारा गाया जाता था जिन्हें गैर-कांग्रेसी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य कर रहे थे। मद्रास में, कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए सत्यमूर्ति ने 9,000 मील का दौरा किया। यहां प्रचार यह था कि "पीले बक्से में मत डालें क्योंकि व्यवहारिक तौर पर सभी कांग्रेसी प्रत्याशियों ने पीले रंग की मतपेटियों का चुनाव किया था। यह बहुत साफ था कि 'जस्टिस पार्टी' चुनाव हार जायेगी। देश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह था। फिर भी, कुछ स्थानों पर कांग्रेस की हालत नाज़ुक थी। उदाहरण के लिए, बंगाल में, "प्रजा कृषक पार्टी" काफ़ी लोकप्रिय थी, और लगभग इसी स्थिति में "यूनियनिस्ट पार्टी" पंजाब में थी। यू० पी० में ज़मींदारों ने चुनाव लड़ने के लिए जल्दबाज़ी में "नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी" का गठन किया लेकिन यह पार्टी मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकी। इन क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस को मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा जैसी साम्प्रदायिक आधार पर राजनीति चलाने वाली पार्टियों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।

30.4.3 चुनाव परिणाम

विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तिथियों में चुनाव हुए थे। चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहे। बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस ने बहुत अच्छी स्थिति दर्शायी। पांच प्रांतों में इसे स्पष्ट बहुमत मिला। (देखिये तालिका1)

तालिका 1

प्रांत	सीटों की कुल संख्या	कांग्रेस को प्राप्त सीटें
यू० पी०	228	134
बिहार	152	95
मद्रास	215	159
सी० पी०	112	70
उड़ीसा	60	36
बम्बई	175	87
बंगाल	250	60
सिंध	60	8
असम	108	35
एन० डब्लू० एफ० पी०	50	19
(उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत) पंजाब	175	18

बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और बंबई में कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयी, जबकि पंजाब और सिंध में इसकी स्थिति कमज़ोर थी। पंजाब की पार्टीवार स्थिति तालिका-2 में और बम्बई की पार्टीवार स्थिति तालिका-3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2 (पंजाब)

कांग्रेस	18
यूनियनिस्ट पार्टी	98
हिन्दू महासभा	12
अकाली	11
खालसा नेशनल पार्टी	13
मुस्लिम लीग	2
अन्य	21
	175

तालिका 3 (बंबई)

ग़ैर-ब्राह्मण पार्टी	8
कांग्रेस	87
मुस्लिम लीग	10
मुस्लिम निर्दलीय	12
निर्दलीय	17
यूरोपीय	6
पीजेंट (किसान) पार्टी	2
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी	13
अन्य	20
	175

उच्च सदनों के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि यहां मताधिकार केवल सभ्रांत वर्ग तक ही सीमित था (देखिये तालिका 4)

तालिका 4
विधान परिषद (उच्च सदन) परिणाम

प्रांत	कुल सीटें	कांग्रेस को प्राप्त सीटें
मद्रास	46	26
बम्बई	26	13
बिहार	26	8
यू० पी०	52	8
बंगाल	57	9

जहां तक सुरक्षित सीटों का सवाल है हम कांग्रेस की स्थिति के कुछ उदाहरण यहां दे रहे हैं (सभी 11 प्रान्तों में)

- मज़दूरों के लिए सुरक्षित 38 सीटों में से कांग्रेस ने 20 पर चुनाव लड़ा और 18 पर विजय प्राप्त की।
- 482 सीटें, मुस्लिम सीटों के रूप में आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 58 पर अपने उम्मीदवार खड़े किये और 26 पर वे जीते इनमें से 19 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की थीं। बम्बई, यू० पी०, सी० पी०, सिंध और बंगाल में कांग्रेस एक भी मुस्लिम सीट प्राप्त नहीं कर सकी। फिर भी, यहां यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं था। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक भी सीट नहीं जीत सकी। पंजाब में 84 आरक्षित सीटों में से इसे केवल दो सीटें प्राप्त हुईं।
- वाणिज्य और उद्योग के लिए 56 सीटें आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 8 पर चुनाव लड़ा और केवल 3 सीटें जीतीं।
- भूस्वामियों के लिए 37 सीटें आरक्षित थीं। कांग्रेस ने 8 पर चुनाव लड़ा और 4 पर विजय प्राप्त की।

इस तरह सुरिक्षत चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन सिवाय मज़दूर सीटों के संतोषप्रद नहीं था, मगर सामान्य सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अपनी चुनावी जीत पर कांग्रेस कार्य समिति ने लोगों को निम्न संदेश दिया:

'कांग्रेस कार्यसमिति हाल के चुनावो में कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की नीतियों के प्रति जन समर्थन का प्रदर्शन करने वाले शानदार प्रत्युत्तर के लिए राष्ट्र को बधाई देती है।''

बोध प्रश्न 3

1 कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए अपनाये गये मानदंडों को क़रीब पांच पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2 निम्न में से कौन सा सही ($\surd$) और कौन सा ग़लत ($\times$) है।

i) पटेल ने एन० जी० रंगा की शपथ का समर्थन किया। ☐

ii) नेहरू कृषि कार्यक्रम को चुनाव अभियान में प्रमुख स्थान देना चाहते थे। ☐

iii) लोगों का विश्वास था कि कांग्रेस राज ब्रिटिश राज का स्थान ले लेगा। ☐

iv) मुस्लिम सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। ☐

v) कांग्रेस ने उच्च सदनों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ☐

30.5 पद स्वीकरण (Office Acceptance)

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पद स्वीकार करने का निर्णय कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों के कारण लम्बित छोड़ दिया गया था। इस मामले पर विचार करने के लिए मार्च, 1937 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। राजेन्द्र प्रसाद ने पद के "सशर्त स्वीकरण" का एक प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। जोड़ी गयी शर्त यह थी कि मंत्रिमंडलों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां जयप्रकाश नारायण ने पद को पूरी तरह अस्वीकार करने का एक प्रस्ताव रखा लेकिन मतदान कराये जाने पर यह प्रस्ताव नामंजूर हो गया (पक्ष में 78 और विरोध में 135 मत) कांग्रेस के अंदर यह दक्षिण पक्ष की बड़ी विजय मानी गयी। स्वयं गांधीजी पद के सशर्त स्वीकरण के पक्ष में थे।

इस बार फिर पद स्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दोहराये गये। मंत्रिमंडल गठित करने के पक्ष में एक मुख्य तर्क यह था कि इसके माध्यम से कांग्रेस किसान और मज़दूरों को कुछ राहत दे सकेगी। लेकिन एन० जी० रंगा, सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याजनिक जैसे नेताओं ने पद स्वीकार करने को साम्राज्यवाद के साथ असहयोग की मूल कांग्रेसी नीति से पीछे हटना बताया। सहजानंद ने महसूस किया कि पद स्वीकारने के पक्षधर अपने आप को निरुत्तर महसूस कर रहे हैं और वे "किसानों का बहाना लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं" और जैसा कि वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्पष्ट किया:

"संसदीय मानसिकता लोगों में घर करने लगी थी"

उन 6 प्रांतों में जहां कांग्रेस बहुमत में आयी थी, गर्वनरों द्वारा इसके नेताओं को मंत्रिमंडल गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गयी शर्तों पर गवर्नरों द्वारा आश्वासन देने से इंकार किये जाने पर इस आमंत्रण को ठुकरा दिया गया। सरकार का अगला क़दम इन प्रांतों में अंतरिम सरकारों का गठन करना था। उदाहरण के लिए, नवाब छतारी ने यू० पी० में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और बम्बई में धनजीशाह कपूर ने मंत्रिमंडल बनाया।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये ऐसे मंत्रिमंडल थे जिनका विधान मंडलों में बहुमत नहीं था। इसलिए ये 6 महीने से ज़्यादा सत्ता में नहीं रह सके। बम्बई में बहुत से कांग्रेसी जो पदस्वीकरण के पक्ष में थे, सरकार के इस क़दम से समझौता नहीं कर सके। कुछ यह भी महसूस करते थे कि क़ायदे से जो उन्हें मिलना चाहिए था उसे दूसरों को दे दिया गया था। इसलिए उन्होंने कार्य समिति पर पद स्वीकार करने के पक्ष में दबाव डालने के लिए ज़ोरदार प्रयास किए। इसी प्रकार की स्थिति राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास में भी पैदा हो गयी। राजगोपालाचारी इस समय तक सत्ता संभालने के प्रबल पक्षधर हो चुके थे। बिहार में, किसान जांच समिति का काम फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन सभाओं में जो बात कही जा रही थी, वह पद स्वीकार करने की थी। यू० पी० में किसानों को लगान न देने के लिए उत्साहित किया गया था, इस आश्वासन के आधार पर कि जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो सारा बक़ाया लगान माफ़ कर देगी।

कम मामलों में गवर्नरों ने (जैसे कि मद्रास के गवर्नर लार्ड एरिस्किन) वाइसरॉय के सामने विधानमंडलों को भंग करने का प्रस्ताव रखा लेकिन, लिनलिथगो महसूस करते थे कि कांग्रेस जल्दी ही घुटने टेक देगी और यह थोड़े ही समय का मसला है। साथ ही उसे यह भी मालूम था कि जो कांग्रेसी पद स्वीकरण के पक्ष में थे उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के फैसले का पालन करने में असाधारण अनुशासन प्रदर्शित किया था। 20 जून को वाइसरॉय ने मंत्रियों की तुलना में गवर्नरों के विशेषाधिकारों के संबंध में सरकार की स्थिति का स्पष्टीकरण दिया। तब वर्धा में जुलाई के पहले सप्ताह में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में पद स्वीकार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत के अधिकांश पूँजीपति कांग्रेस द्वारा पद

चित्र 13. गोविन्दवल्लभ पंत

स्वीकार किए जाने के पक्ष में थे। जी० डी० बिड़ला इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। और निरंतर कांग्रेसी नेताओं के सम्पर्क में थे। जब गांधीजी ने अंतिम रूप से पद के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी तो बिड़ला ने महादेव देसाई को लिखा था:
मेरा मन मुझे यह भरोसा करने के लिए गुदगुदा रहा है कि बापू के मन को प्रभावित करने में मेरे पत्रों का भी कुछ योगदान रहा होगा।

सरकार को कांग्रेस के निकट लाने के लिए बिड़ला इतने अधिक उत्सुक थे कि उन्होंने गांधीजी के वक्तव्य के बारे में स्टेट सेक्रेटरी लार्ड जैटलैंड को सूचित किया था कि "पदस्वीकरण एक ओर तो **ख़ूनी क्रान्ति** को और दूसरी ओर व्यापक नागरिक अवज्ञा को रोकने का प्रयास था"।

अंतरिम मंत्रिमंडलों के पद त्याग के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। यह स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नये युग की शुरुआत थी।

प्रांत	कांग्रेसी प्रधानमंत्री
बम्बई	बी० जी० खैर
यू० पी०	गोविंद वल्लभ पंत
मद्रास	सी० राजगोपालाचारी
उड़ीसा	हरेकृष्ण महताब
सी० पी०	डा० खरे
बिहार	श्री कृष्ण सिन्हा
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत	डा० ख़ान साहब

बंगाल में मिली-जुली सरकार बनाने में सहयोग करने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया। कांग्रेस ने इंकार कर दिया तो हक़ ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लिया। सिंध में कांग्रेस ने ग़ुलाम हुसैन हिदायत उल्ला के मंत्रिमंडल को, और असम में बरदोलाई के मंत्रिमंडल को समर्थन दिया। पंजाब में कांग्रेस कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थी।

कांग्रेस ने पद स्वीकार करने के फैसले में 6 महीने का विलम्ब किया था। **रवि धवन शंकर वास** के अनुसार (द फर्स्ट कांग्रेस राज 1982) इस विलम्ब से कांग्रेस को निम्नलिखित लाभ हुए:

i) इस विलम्ब में चुनाव के समय के कांग्रेस विरोधी इस प्रोपेगैंडा को झुठला दिया कि कांग्रेसी पद के भूखे हैं, और मंत्रिमंडल बनाने का पहला मौक़ा मिलते ही इसे लपक लेंगे।
ii) कांग्रेस की एकता बनी रही और यह लोगों के सामने आयी।
iii) गवर्नरों और मंत्रियों के सामने यह बात स्पष्ट हो गयी कि कांग्रेस हाईकमान का निर्णय ही सर्वोच्च था।
vi) मंत्रियों के कामकाज में दख़ल देने से पहले गवर्नरों को कई बार सोचना पड़ता था।

30.6 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कामकाज

कांग्रेस के सामने जो काम था वह बहुत विशाल था। ख़ासतौर से उन अपेक्षाओं के कारण जो लोग कांग्रेस से उम्मीद रखते थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के एक-एक दिन का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के बजाए हम यहां विषयगत रूप से यह बताना चाहेंगे कि अपने लगभग ढाई वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया।

30.6.1 राजनीतिक क़ैदी और नागरिक स्वतंत्रताएं

कांग्रेस अपने चुनाव के घोषणा पत्र के माध्यम से, राजनीतिक क़ैदियों और नज़रबंदियों की रिहाई के लिए वचनबद्ध थी। इनमें से बहुत से बिना मुकद्दमा चलाये जेलों में रखे जा रहे थे। अडंमान के क़ैदियों ने गांधीजी को लिखा था कि उनका अब हिंसा के रास्ते में विश्वास नहीं रहा । सबसे अधिक राजनीतिक कैदी बंगाल में थे, जो एक ग़ैर कांग्रेसी शासन वाला प्रांत था। उनकी मुक्ति की बातचीत के लिए गांधीजी स्वयं कलकत्ता गये। 3 सप्ताह की लम्बी बातचीत के बाद उन्हें 1100 नज़रबंदियों की रिहाई कराने में सफलता मिली। यू०पी० में बहुत से क़ैदियों को मुक्त किया, जिनमें से प्रमुख थे, काकोरी कांड के बंदी। इन क़ैदियों के स्वागत में व्यापक जन प्रदर्शन हुए लेकिन अंग्रेज़ सरकार को यह सब पसंद नहीं आया। गांधीजी, गोंविन्द वल्लभ पंत, और जवाहरलाल नेहरू ने क़ैदियों की रिहाई का स्वागत किया। मगर उनके स्वागत आयोजनों की आलोचना की। पंत का मानना था जनता का इस प्रकार का प्रत्युत्तर अन्य क़ैदियों की रिहाई में बाधा पैदा कर सकता था और हुआ भी यही। यू०पी० और बिहार के गवर्नरों ने क़ैदियों की मुक्ति पर रोक लगा दी। हरीपुरा अधिवेशन (मार्च, 1938) से ठीक पहले इन प्रांतों के प्रधानमंत्रियों ने इस मुद्दे पर त्यागपत्र दे दिए। हरीपुरा में कांग्रेस की स्थिति स्पष्टता से रखी गयी कि वह हिंसात्मक अपराध के मामले में कार्रवाई करने में झिझकेगी नहीं, लेकिन क्योंकि क़ैदी हिंसा को त्याग चुके थे इसलिए उन्हें मुक्त करने में कोई ख़तरा नहीं था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा।

कांग्रेस ने रासबिहारी बोस, पृथ्वी सिंह, मौलवी अब्दुल्ला ख़ान, अबाली मुखर्जी इत्यादि राजनीतिक निर्वासितों के भारत आने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए भी कोशिशें की, परंतु कांग्रेस इस दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी।

कांग्रेस अहिंसा के दायरे में नागरिक स्वतंत्रताओं से भी प्रतिबद्ध थी। सितम्बर, 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया:

> "....कांग्रेस जनता को चेतावनी देती है कि नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हिंसात्मक कृत्य, हिंसा के लिए उकसाने, या खुले झूठ के प्रचार आदि के काम नहीं आते" यह स्पष्ट कर दिया गया कि "कांग्रेस अपनी परम्पराओं के अनुकूल उन उपायों का समर्थन करेगी जो कांग्रेस सरकारों द्वारा जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाये जा सकते हैं"

कांग्रेस का वामपंथी धड़ा इस प्रकार के दृष्टिकोण का विरोधी था, और, इस प्रस्ताव को कांग्रेस में वामपंथियों की हार के रूप में लिया गया।

30.6.2 किसानों का सवाल

किसानों की समस्या एक ज्वलंत सवाल के रूप में मौजूद थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "भारत की एकमात्र सबसे बड़ी समस्या किसान समस्या है। बाक़ी सब दूसरे नम्बर पर आता है।" उनका विश्वास था कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन होने से किसानों में नयी उम्मीदें जागी हैं, जबकि "बड़े ज़मींदार और ताल्लुकेदार किसानों को उनका न्यायपूर्ण हक़ मिलने से रोकने के लिए संगठित हो रहे हैं" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अपने वादों के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए और किसानों की उम्मीदों को पूरा और संतुष्ट करना चाहिए। किसान सभा ने 1935 में कांग्रेसी अध्यक्ष के इस प्रकार के वक्तव्य का स्वागत किया। कांग्रेस शासित सभी प्रांतों में काश्तकारी विधेयक लाया गया। दक्षिणपंथी गुट ज़मींदारों से बातचीत किये बिना इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। यह स्थिति हर प्रांत में भिन्न थी। उदाहरण के लिए, बिहार में काश्तकारी विधेयक के प्रावधानों को लेकर कांग्रेस ने ज़मींदारों के साथ एक समझौता किया। इस समझौते को सम्पन्न कराने में मौलाना आज़ाद और राजेन्द्र प्रसाद की प्रमुख भूमिका रही। बिहार किसान सभा की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गयी। इस विधेयक की न केवल वामपंथी धड़े ने कटु आलोचना की बल्कि किसान हितों से सहानुभूति रखने वाले दूसरे कांग्रेसियों ने भी इसकी आलोचना की। प्रसाद ने दरभंगा के महाराज को लिखा था कि "उनकी न केवल किसान सभा द्वारा भारी आलोचना की जायेगी बल्कि आमतौर पर कांग्रेस और शायद हाईकमान द्वारा भी आलोचना की जायेगी।" यही वह

समय था जब कांग्रेसियों के किसान सभा की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिहार में कांग्रेस की नीति एक हद तक ज़मींदारी समर्थक थी। ज़मींदारों को भरोसा था कि उनकी ख़ातिर ही कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन को दबाया जा रहा है। दूसरी ओर, किसान सभा में कांग्रेस को फ़ैज़पुर कृषि कार्यक्रम लागू करने की याद दिलाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कई संघर्ष शुरू कर दिये।

यू० पी० में हालत बिहार से भिन्न थी। यू० पी० कांग्रेस में वामपक्ष का अधिक बोलबाला था। जो काश्तकारी विधेयक यहां पारित हुआ, उसे इसके पारित किये जाने के दो साल बाद तक भी गवर्नर का अनुमोदन नहीं मिला।

बम्बई में कांग्रेस उस भूमि को जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन के "लगान नहीं" अभियान के परिणामस्वरूप नये स्वामियों को बेच दी गयी थी, उसे उनके मूल स्वामियों को वापस दिलाने में कामयाब हुई।

सभी प्रांतों में किसानों को साहूकारों से बचाने और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किये गये। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ज़मींदार मज़बूत स्थिति में रहे। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में कालीकोट के ज़मींदार ने रिज़र्व पुलिस के लॉरी सवार जवानों की परेड, किसानों को यह चेतावनी देने के लिए करवायी गयी कि वह कांग्रेसी शासन में भी उतना ही ताक़तवर है जितना कि पहले था लेकिन कुल मिलाकर यह किसानों के बीच ज़बरदस्त जागृति का समय था, और ये किसान कांग्रेस के पीछे थे।

नया क़ानून

पिछले चुनाव में काँग्रेस ने किसानों और छोटे छोटे ज़मींदारों के फ़ायदे के लिये कानून बनाने का वादा किया था। ८ महीने की लगातार कोशिश और तहकीकात के बाद हमारे प्रान्त के कांग्रेसी मंत्रि मंडल ने पिछले कानून लगान और कानून मालगुजारी की जगह पर जो नये कानून का मसविदा तैयार किया है उसकी मोटी मोटी बातें छाप कर आपकी सेवा में भेजी जाती हैं और यह आशा की जाती है कि आप इस पर अच्छी तरह विचार करेंगे और जल्द से जल्द अपने अपने गांव वालों की और अपने यहाँ के मंडल और ज़िला कांग्रेस कमेटियों की जो भी राय इन तजवीज़ों पर होगी उसे नीचे लिखे पते पर भेजने का कष्ट करेंगे॥

महावीर त्यागी
मंत्री
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, लखनऊ।

.....
मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली

साहित्य-मन्दिर प्रेस लि०, लखनऊ।

चित्र 14. यू० पी० काश्तकारी विधेयक के मसौदे पर कांग्रेस के नेताओं के बयान

महकमे माल के मंत्री

श्री रफ़ीअहमद किदवाई का वक्तव्य

किसानों का जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है वे लगान के बोझ से दबे हुए हैं। जमीन पर उनका हक़ सुरक्षित नहीं है क्योंकि वे अनेक बहानों से बेदखल किये जा सकते हैं। कभी-कभी उनसे ऐसी नाजायज़ रक़में वसूल करली जाती हैं जो सौर क़ानूनी हैं ।

जो नई तजवीजें हम पेश कर रहे हैं उनसे ये सब ज्यादतियाँ रुक जायेंगी। तमाम किसानों को मौरूसी हक़ दिये जायेंगे। लगान की नादेंहदी के सिवा, वे किसी और कारण से बेदखल नहीं हो सकेंगे। लगान की दर बदल दी जायगी और लगान की कमी बेशी क़ानून के जरिये हुआ करेगी, किसानों को अपनी जमीन पर पेड़ लगाने और मकान बनाने के हक़ होंगे। जमींदार किसानों से जो भी रक़म वसूल करेगा उसकी रसीद लाज़िमी देनी पड़ेगी। क़ानूनी लगान के सिवा और तमाम मुतालबे नाजायज़ होंगे।

मैं जानता हूँ कि इनके अलावा किसानों के और भी कई गंभीर मसले हैं, जिनका ज़िक्र इस मसौदे में नहीं आया। उनके लिये भी अलग क़ानून बनेंगे।

इसके फौरन ही बाद क़र्ज़े का सवाल हल किया जायगा। इसी तरह आबादी के संबंध में भी क़ानून बनाये जायेंगे। ये तो सिर्फ काश्तकारी हक़ का मसौदा है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मसविदे से किसानों की तक्लीफें बहुत हद तक दूर होंगी।

लखनऊ। आपका

१० अप्रैल १९३८ रफ़ीअहमद क़िदवाई

चित्र 14. यू० पी० काश्तकारी विधेयक के मसौदे पर कांग्रेस के नेताओं के बयान

30.6.3 मज़दूर

कांग्रेस ने श्रमिक वर्ग से बेहतर कार्य दशाओं का वादा किया था। मगर इसकी श्रमनीति वामपक्ष और दक्षिणपक्ष के बीच परस्पर संबंधों से प्रभावित थी। दक्षिणपक्ष का विश्वास था कि मज़दूरों और पूंजीपतियों का रिश्ता न्यासिता (ट्रस्टीशिप) के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वामपक्ष इस रिश्ते को वर्गीय समीकरण पर आधारित करता

था। अक्तूबर, 1937 में कांग्रेस द्वारा नियुक्त मज़दूर समिति (लेबर कमेटी) ने एक कार्यक्रम दिया जिसे ए.आई.सी.सी. (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

- वेतन सहित छुट्टियां
- रोज़गार बीमा
- बीमारी के दौरान सवेतन अवकाश
- न्यूनतम वेतन निर्धारण का रास्ता खोजना
- शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीकों की नीति पर चलने वाले श्रमिक संगठनों (ट्रेड यूनियनों) को राज्य से मान्यता दिलवाना।

तथापि, बम्बई ही अकेला ऐसा प्रांत था, जहां श्रम संबंधी विधेयक लाया गया। मंत्रिमंडल ने जहां तक संभव हुआ हड़ताल और तालाबंदी रोकने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया। मज़दूरों के अनुसार इसका मतलब केवल हड़तालों पर रोक लगाना था क्योंकि तालाबंदी मज़दूरों के शोषण के लिए पूंजीपतियों के तरकश का सबसे तीख़ा तीर था। जिसके विरुद्ध सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसे लेकर मज़दूरों ने हड़ताल की जिसे कांग्रेस सरकार ने पुलिस की मदद से कुचल दिया। पुलिस कार्रवाई में क़रीब 20 मज़दूर मारे गये।

इसी समय कानपुर में मज़दूरों की व्यापक हड़ताल हुई। यहाँ अगस्त, 1934 में 24,000 मज़दूरों ने अधिक वेतन और बेहतर जीवन स्थितियों की मांग को लेकर काम ठप्प कर दिया। इस हड़ताल की भी कांग्रेस द्वारा आलोचना की गई। जब मज़दूरों ने धरना शुरू किया तो नेहरू ने कहा:

अगर हिंसा का सहारा लिया जाता है तो यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और सेना या पुलिस को नहीं बुलाया जाएगा। मज़दूरों को याद रखना चाहिए सरकार बहुत शक्तिशाली है और हिंसा को दबा देगी और यह कि मज़दूरों का कुछ ही देर में दमन कर दिया जाएगा।

अंत में यह विवाद मंत्रिमंडल द्वारा निपटाया गया।

दूसरी तरफ़ बंगाल में कांग्रेस ने जूट मिलों की हड़ताल (मार्च-मई, 1937) का समर्थन किया। बंगाल पी० सी० सी० (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) ने हक़ सरकार जो कि एक गैर कांग्रेसी सरकार थी, के द्वारा जूट मज़दूरों के दमन की निंदा की। जमशेदपुर में टिसको (टाटा इस्पात कंपनी) श्रमिकों की हड़ताल के दौरान नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद ने टाटा और मज़दूरों के बीच पंच की भूमिका निभाई। इस दौर में वामपंथ ने मज़दूरों पर अपने प्रभाव में वृद्धि की।

30.6.4 रचनात्मक कार्यक्रम

सभी कांग्रेस शान्ति प्रांतों में मद्यनिषेध लागू करने, शिक्षा को प्रोत्साहित करने और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास किए गए। इनमें कुछ प्रमुख काम थे:

- मद्यनिषेध यानी नशाबंदी के पक्ष में ज़ोरदार अभियान चलाना।
- मद्रास मंत्रिमंडल द्वारा खादी और हाथ की कताई के कपड़े के लिए दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाना।
- अस्पतालों में मानद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति।
- सार्वजनिक इमारतों के निर्माण में निवेश को पर्याप्त रूप से कम करना।

शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक क़दम उठाया गया। वर्धा में (22 और 23 अक्तूबर, 1937 को, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एक योजना तैयार की जिसमें निम्न बातें शामिल थीं:

- देश भर में 7 वर्ष के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाए।
- व्यावसायिक और दस्तकारी प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जाए।

इन दिशा निर्देशों के आधार पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के क्रियान्वयन के लिए डॉ० ज़ाकिर हुसैन ने प्राथमिक शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की (2 दिसम्बर, 1937) इस योजना में मान्य

PROGRESS OF WARDHA SCHEME

[The following note has been prepared by Shrimati Ashalata Devi. M. K. G.]

Bihar

A training centre with sixty students and eight teachers has been started in the Training School, Patna, for a six months' emergency training course, and a compact area has been selected for experiment in the Bettiah thana of the Champaran District, where 50 Basic Schools will be started from March 1939.

Orissa

A Basic Education Committee consisting of both official and non-official members has been appointed by the Government, with Sjt. Gopabandhu as chairman, to take the necessary steps for the introduction of Basic Education in the province. Eight workers have been selected by the Government and sent to Wardha to be trained as training school teachers and supervisors. One of the party is Smt. Annapurna Chowdhuri, the daughter of Sjt. Gopabandhu Chowdhuri.

A training school with one year's course will be opened in April 1939, and Basic Schools will be opened in April 1940 in a selected compact area.

C. P.

160 pupil teachers are receiving a further training of two months in the training school while the school-building and equipment is being got ready for starting Vidya Mandirs. It is hoped that one hundred schools will be ready by the end of December, and will start work with the new year.

A committee consisting of C. P. educational officers and local members of the Hindustani Talimi Sangh has been formed by the Government to guide the work of the training school.

Madras

The Government has deputed three trained teachers, including the headmaster of a training school, to undergo two months' training in Wardha. The secretary is meeting the Education Minister on Nov. 5th and 6th, to discuss further details regarding the introduction of Basic Education in the province.

A private training school with forty students has been organised at Masulipatam attached to the Andhra Jatiya Kalasala and is doing very good work.

Bombay

The Education Minister has accepted the plan submitted by the secretary for the introduction of Basic Education in the three linguistic provinces of Maharashtra, Karnatak and Gujarat and is sending the Education Secretary Sjt. Gandhi to Wardha towards the end of November to discuss further details.

Kashmir State

A short reorganisation course organised for all teachers and inspectors to acquaint them with the principles of the Wardha Scheme has been successfully completed, and a training school has been opened to train teachers according to the Wardha Scheme of Education.

Mysore State

A Wardha Education Committee has been formed. The secretary has been invited to preside over the first conference and open the first experimental school on November 2nd. and 3rd

TRAINING IN PALM-JAGGERY

Under the auspices of the A. I. V. I. A. the class for imparting training in palm-jaggery making has been started for the current season from 1st November 1938, at Segaon, near Wardha. The course is for a month. Tapping is not included in it. Only the process of gur making is taught. The students have to do practical work for about 7 hours a day. Theory is taught for an hour daily, for acquainting the students with the various aspects of the industry, including its botany, chemistry, commerce, history, economics etc. The students must be strong enough to stand the rigour of the practical work. A fee of Rs. 5 is charged per student. The boarding charges will be about Rs. 8 and Re. 1 for lodging. A deposit of Rs. 15 is required to cover the said expenses and of Rs. 10 for ensuring return journey expenses. The class will be closed on 31st March 1939. Intending candidates should apply for admission to the Secretary, Training School Committee, A. I. V. I. A., Maganvadi, Wardha (C. P.), and should not proceed before obtaining a permission in writing.

Segaon, 14-11-38 Gajanan Naik
Supervisor, Gur Department,
Segaon, Wardha

SUBSCRIPTION RATES

INLAND

One Year, post free	Rs. 4
Six Months "	Rs. 2-8

FOREIGN

One Year, post free	Rs. 5-8
	foreign Sh. 8

CONTENTS

			Page
CONGRESS AND KHADI	...	M. K. Gandhi	333
THE PEOPLE'S EDUCATION MOVEMENT	...	T. H. Tao	334
A CORRECTION	...		335
KHUDAI KHIDMATGARS AND BADSHAHKHAN	...	M. K. Gandhi	336
OCCASIONAL NOTES	...	M. D.	338
IN THE FRONTIER PROVINCE—V		Pyarelal	341
PROHIBITION IN SALEM	...		344
PROGRESS OF WARDHA SCHEME			345
TRAINING IN PALM GUR	...	Gajanan Naik	345

Printed and Published by Anant Vinayak Patwardhan at the Aryabhushan Press, House No. 915/1 Fergusson College Road, Poona 4

हरिजन में प्रकाशित वर्धायोजना की प्रगति (19.11.1938)

To the Readers

Reg. No. B 3092

HARIJAN

Editor : MAHADEV DESAI

Under the Auspices of The Harijan Sevak Sangh

VOL. VI, No. 33] POONA — SATURDAY, SEPTEMBER 24, 1938 [ONE ANNA

CORRUPTION IN THE CONGRESS

(By M. K. Gandhi)

It is difficult to cope with the correspondence that I am having from several places about violence, untruth and corruption in the Congress. Whilst I must continue to publish typical correspondence about the weaknesses of Congressmen, I must issue a warning against hasty deduction being drawn that all is ill with the Congress. I know it is not. But it is true that violence, untruth and corruption have made inroads enough to warrant drastic measures in order to prevent decay overtaking the great organisation.

Here are extracts from two typical letters :

(1) " Perhaps you are aware how the enrolment of bogus Congress members is going on unimpeded everywhere, and how rich and unscrupulous persons are controlling the affairs of the Congress organisation, keeping skilfully the genuine and devoted workers out of their way. Some are paying the membership subscription of annas 4 for others under their control out of their own pockets, and some are going a step forward and are not paying a single pie to the Congress Committees and instead making the Primary Committees under their clutches prepare false accounts of their apparent collections and thereby evading the supervising eye of the Sub-Divisional as well as District Committees.

Primary Committees having less than 25 members are not required, under the rules framed by it, to pay anything to higher Committees out of the membership fee. The result is that a good many paper Committees are being set up with less than 25 members to deprive the Sub-Divisional and District Committees of their quota of the membership subscription as also to secure a larger proportion of representation in these Committees. "

(2) " It is my duty to bring to your notice the open and scandalous corruption in enrolling Congress members. The Congress authorities here, especially the Executives, know this state of things well, but it is difficult to know why the necessary steps are not being taken. If steps are not taken, things will go from bad to worse and the whole Congress Institution will be disgraced and the hold on people will be lost.

(i) Every party is trying to capture the Congress Office — whether Primary, Sub-divisional, District or Provincial. And for this purpose bogus members are being enrolled by practically every group.

(ii) There are a good many names of persons on the Congress rolls, but on scrutiny it can be easily found out that there are no such persons in existence at all. During election time the same group of persons is mobilised at elections of Primary Congress Committees of different wards.

(iii) The members are enrolled sometimes without their own signatures on application forms and in most cases without taking payment of the annual subscription of four annas.

(iv) The question arises how the account of collection of subscription by the Primary, Sub-divisional and District Congress Committees is maintained. In almost all cases where a group is in possession of the office and necessarily the office account, collection of the annual subscription for all the bogus members is shown to the credit side, and at the same time nearly the whole amount is shown to the debit side on the different heads of expenses, such as travelling expense, meeting expense, allowance expense, etc. Really they do not collect the subscription and maintain a false account.

I do not know how all these corruptions can be stopped. There will be, I hope, changes of rules at the next A. I. C. C. meeting at Delhi. Some steps should be immediately taken to stop the corruption. Identification of Congress members, signatures of the members on the application forms, actual realisation of subscription from the members, and true accounts should be enforced.

These statements have been made by responsible parties. The letters are meant for publication. But I have purposely suppressed the names of my correspondents as also of the province in which the corruption is said to exist.

It is to be hoped that the Working Committee and the A. I. C. C. will deal with this as well as the other serious questions that will come up for discussion and decision. It would be a tragedy if the session of the A. I. C. C. were to be frittered away in orations or mutual wranglings.

चित्र 16. कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर हरिजन में छपा गांधी जी का लेख

दस्तकारी, मातृभाषा का उचित ज्ञान, आधारभूत शिक्षा शामिल थी। कई प्रांतों में इस योजना को लागू करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस की शिक्षानीति के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, बम्बई प्रांत में 1936-37 में शिक्षण संस्थाओं की संख्या 14,609 थी और 1939-40 तक यह बढ़कर 18,729 हो गई थी। इसी प्रकार 1936-37 में विद्यार्थियों की संख्या 13,35,889 थी जो 1939-40 में बढ़कर 15,56,441 हो गई।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की अन्य प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं:

- मंत्रियों के वेतन में कटौती,
- मूल अधिकारों की घोषणा,
- जेलों की स्थितियों में सुधार,
- आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं,
- दमनकारी कोयला क़ानून की समाप्ति,
- वाणिज्य और आर्थिक सर्वेक्षण कराना।

इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता सरकारी अधिकारियों के रुख़ में परिवर्तन था। अब उन्हें नेताओं के अधीन काम करना पड़ा जिन्हें वे पहले गिरफ़्तार किया करते थे।

30.6.5 कांग्रेस के सामने आई कुछ समस्याएं

सांप्रदायिक पार्टियों द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव बरतने का आरोप लगाया लेकिन दुष्प्रचार तथ्यों पर आधारित न होकर राजनीतिक और साम्प्रदायिक कारणों पर खड़ा किया गया था। साथ ही, इस समय पद का लाभ उठाने की ग़रज़ से बहुत से अवसरवादी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ऐसे तत्वों को पहचानती थी और गांधीजी ने कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार के बारे में अपने अख़बार (हरिजन) में स्पष्टता से लिखा था। कई क्षेत्रों में कांग्रेस को ऐसे तत्वों से मुक्त कराने का अभियान भी चलाया गया। इस समय कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए। 51वां अधिवेशन हरिपुरा में फ़रवरी, 1938 में सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन ने राष्ट्रीय मामलों और अंतर्राष्ट्रीय मसलों से संबधित कई प्रस्ताव पारित किए। लेकिन कांग्रेस ने असली संकट का सामना त्रिपुरा अधिवेशन में किया। इस बार अध्यक्ष पक्ष के लिए चुनाव हुए और सुभाषचंद्र बोस ने पट्टाभिसीतारमैय्या को 1337 के मुक़ाबले 1580 मतों से पराजित किया। इसे वामपक्ष की विजय माना गया क्योंकि दक्षिण पक्ष ने सीतारमैय्या को एकजुट समर्थन दिया था। स्वयं गांधीजी ने भी इस हार को अपनी हार माना था। इससे

चित्र 17. हरिपुरा में नेहरू तथा बोस

कार्यसमिति के गठन करने में परेशानियाँ आई तब आख़िर में बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने नवम्बर, 1939 में सरकार से इस आधार पर त्याग पत्र दे दिया कि वाइसरॉय ने बिना कांग्रेस से पूछे अपनी मर्ज़ी से ही भारत को सम्राज्यवादी युद्ध में भागीदार बना दिया था।

बोध प्रश्न 4

1 पद स्वीकरण के मसले पर विलम्ब करने से कांग्रेस ने क्या हासिल किया? लगभग पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2 निम्न में से कौन से कथन सही (√) या ग़लत (×) हैं।

i) पूंजीपति पद स्वीकरण के विरोध में थे। ☐

ii) गांधी सशर्त पद स्वीकरण के पक्ष में थे। ☐

iii) फज़लुलहक़ ने मंत्रिमंडल बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। ☐

iv) कांग्रेस ने राजनीतिक क़ैदियों की मुक्ति के लिए क़दम उठाए। ☐

v) बिहार में कांग्रेसियों पर किसान सभा में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ☐

vi) बम्बई के मज़दूर वर्ग ने औद्योगिक विवाद विधेयक का विरोध किया। ☐

3 किसानों के प्रति कांग्रेस के रुख़ का लगभग दस पंक्तियों में वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30.7 सारांश

इस इकाई में हमने पढ़ा है कि किस तरह कांग्रेस ने एक लम्बी बहस के बाद चुनाव लड़ने का निर्णय किया, और किस तरह वह पांच प्रांतों में विजयी हुई। कांग्रेस की जीत का श्रेय इसकी जन-समर्थक नीतियों को दिया गया। कई मामलों में ज़मीदारों और साम्प्रदायिक ताक़तों ने कांग्रेस का विरोध किया। हालांकि कांग्रेसियों के बीच चुनावों में भाग लेने और बाद में पद स्वीकरण के सवाल पर मतभेद थे, परंतु जब एक बार निर्णय ले लिया जाता था तो सभी दृढ़ता से उसका पालन करते थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कुछ सीमाओं के बींच काम लिया, परन्तु उन्होंने लोगों को राहत दिलवाने के श्रेष्ठतम प्रयास किए। इस दौर में रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा मिला। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के गठन को लोगों ने अपने ख़ुद के "राज" के रूप में लिया। उनको पूरा भरोसा हो गया था कि अब ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने हैं यद्यपि कांग्रेस के भीतर वामपक्ष काफ़ी मुखर था, फिर भी पार्टी में दबदबा दक्षिण पक्ष का ही था।

30.8 शब्दावली

नागरिक स्वतंत्रताएं (Civil Liberties) : सरकार द्वारा लोगों को दी गई जान, माल, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताए।

अंतरिम मंत्रिमंडल (Interim Ministries) : जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठित करने से इंकार कर दिया तो सरकार ने दूसरों को मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। परिषदों में इन मंत्रिमंडलों को बहुमत का समर्थन नहीं था। इन्हें अस्थायी उपाय के रूप में बनाया गया था।

घोषणा पत्र (Manifesto) : एक राजनीतिक पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों की प्रकाशित घोषणा।

पद स्वीकरण (Office Acceptance) : यहां यह शब्द मंत्रिमंडल के गठन के लिए सहमत होने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।

मद्यनिषेध (Prohibition) : मद्यनिषेध या नशाबंदी का मतलब शराब की बिक्री या उसके पीने पर प्रतिबंध से है।

30.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1 स्वराजवादियों ने संविधान को अंदर से ध्वस्त करने के लिए परिषदों में प्रवेश किया था जबकि इस समय पद स्वीकरण की वकालत करने वाले सुधारों को सफल बनाना चाहते थे। भाग 30.2 देखें।

2 i) (×) ii) (×) iii) (√) iv) (√) v) (×)

बोध प्रश्न 2

1 कांग्रेस अपने जनाधार की परीक्षा कर सकी, उसने चुनावों का अनुभव प्राप्त किया और अपने सहयोगियों की परीक्षा की। उपभाग 30.3.1 देखें।

2 उपभाग 30.3.2 देखें।

3 उपभाग 30.3.4 देखें।

बोध प्रश्न 3

1 इस मापदंड के अनुसार प्रत्याशियों की लोकप्रियता, कांग्रेस के प्रति उनकी सेवाओं, कांग्रेस के अनुशासन का पालन, इत्यादि पर विचार किया गया। उपभाग 30.4.1 देखें

2 i) (×) ii) (√) iii) (√) iv) (×) v) (√)

बोध प्रश्न 4

1 भाग 30.5 देखें।

2 i) (×) ii) (√) iii) (×) iv) (√) v) (×) v) (√)